लखनऊ से प्रकाशित राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक
website: www.pawanprawah.com
पेज-12
पवन प्रवाह
सत्य का प्रवाह सतत् प्रवाह
डाक पंजीयन संख्या GPO LW/NP-106/2018-2020

कंगना का नया अवतार

लेखक डॉ- भरत राज सिंह
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइसेज के महानिदेशक
एवं वैदिक विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष हैं

पर्यावरण की विनाशकारी परिस्थिति पर नकारात्मक सोच - एक बहस

हम पूर्व अंक-4 (चार) मे अमरीकी डोनाल द्रम्प के 22 नवम्बर 2018 ट्वीट पर बताया कि अमेरिका मे वर्तमान मे तापमान शून्य से दो डिग्रीसेंटीग्रेड कम चल रहा है और वैज्ञानिक कह रहे कि यहा ग्लोबल-वार्मिंग का प्रभाव है। वह 2017 मे भी वैश्विक-तापमान की बढोत्तरी तथा कैलिफोर्निया में जंगलो की आग पर ठीकरा वैज्ञानिको फोडा। आइये आगे पढ़िये अमेरिका के राष्ट्रपति के अनुसार पर्यावरण असंतुलन से सम्भावित विनाशकारी प्रभाव क्या पड़ेगा।

भाग-05

गतांक से आगे

पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव

अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प ने पर्यावरण और अमेरिका की जलवायु नीतियों के बारे में कई तरह की टिप्पणियां पूर्व मे की हैं, उनमें से ग्लोबल वार्मिंग को चीनियों द्वारा बनाई गई एक धोखाधडी की संज्ञा दी है और कहा कि पर्यावरणीय संरक्षण नीति (ईपीए) एक कलन्क है और इसे खत्म करने की आवश्यकता है तथा अमरीकी राज्य को वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों से खतरा है।

सारा पॉलिन के 2008 के अभियान को ड्रिल, बेबी, ड्रिल कहना शुरू कर देती है, जो लगभग सहज लगता है। लेकिन उनकी यह अपरिपक्व टिप्पणी, पर्यावरण और वैज्ञानिक समुदाय के लोगों के लिए कोई हंसी की बात नहीं है, जो लोग इसके लिए समर्पित हैं और ग्रह की अनिश्चित स्थिति का अध्ययन करने के लिए जीवन को लगा रहे हैं।

फ्रांस में रह रहे यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के स्थायी पर्यटन कार्यक्रम के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, पीटर डेब्रिन कहते हैं कि - लोगों ने सोचा कि ब्रिटेन से बाहर जाने (ब्रेक्सिट) जैसा संदेश पुनः नहीं होगा, लेकिन ट्रम्प का संदेश भी उन जैसे बहुत से लोगों के साथ मेल खाता है। इस तरह की बात ब्रिटेन में हुई थी, इसलिए जो लोग डरे हुए हैं उन्हें कम मत समझिए। हमें इसी तरह से समझना और जवाब देना होगा, जैसा कि उन लोगों को महसूस हो रहा है होगा और सुना जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को राष्ट्रपति चुने जाने व चुनाव के परिणाम की घोषणा के पूर्व; देश भर के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने संभावित पर्यावरणीय प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त की थी। जिसका कुछ अंश निम्नलिखित रूप मे है:

रक्षा विभाग (डीओडी) जो पहली गैर-पर्यावरणीय अमेरिकी एजेंसियों में से एक थी, उसने एक रिपोर्ट जारी की कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक और अपार चिंता का विषय है। पिछले दो-वर्ष पूर्व 2016 की जुलाई में जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अति आवश्यक व बढ़ता हुआ खतरा है, जो प्राकृतिक आपदाओं, शरणार्थी प्रवाह में वृद्धि, और भोजन और पानी जैसे बुनियादी संसाधनों पर संघर्षपूर्ण कार्य के लिये चिंता पैदा करता है। रिपोर्ट पर यदि विशेष ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि ये प्रभाव जो पहले से ही हो रहे हैं, समय के साथ उन ऐसी समस्याओं का दायरा, पैमाना और उनकी तीव्रता मे बढ़ोत्तरी निरन्तर होती जाएगी।

पेंटागन के अधिकारियों ने इस रिपोर्ट में कहा है कि जलवायु परिवर्तन सुरक्षा के लिये एक जोखिम है; क्योंकि यह मानव सुरक्षा और सरकारों की उनकी आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के साथ-साथ रिहायसी स्थिति को भी खराब करता दिखाता है।

फरवरी में क्या कुछ अधिक हुआ है- पेंटागन ने जलवायु परिवर्तन पर रूपांतरण और लचीलापन नामक एक नयी नीति का निर्देश जारी किया है, जो शीर्ष पदो पर आसीन कमांडरों को जलवायु परिवर्तन नीति को लगभग हर एक चीज जो आप कर रहे है, उनको शामिल करने का निर्देश देता है। और डीओडी एक ऐसी संस्था नहीं है जो अग्रणी बनकर राय व्यक्त करती हो अथवा बृक्षो जैसे एक दूसरे को आलिंगन करते हुये उदारवादिता के लिए जानी जाती हो।

ट्रम्प की स्थिति यह है कि वह डीओडी के प्रयासों को बहुत कम आकलन करने के लिए तत्पर हैं और नही उन्हे जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ा विश्वास है और वह पिछले आठ वर्षो के दौरान, जलवायु परिवर्तन के संबंध में लागू की गई, सभी पर्यावरणीय नीतियों को वापस ले सकते है। मैनहट्टन कॉलेज के सरकारी विभाग के अध्यक्ष और पृथ्वी वार्ता बुलेटिन के संपादक-पाम चेसक कहते हैं कि रक्षा विभाग (डीओडी) ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, और वह सौर और पवन पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास वार्ता समिति ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने ऐसा करने में बहुत निवेश कर रखा है और वे यह सब कुछ रोकने नही जा रहे हैं। चूकि इस कार्य में पहले से ही हो रहे हैं। अतः कोई भी राष्ट्रपति इसे बदल नहीं सकता है क्योकि इसका आर्थिक प्रभाव विनाशकारी होगा।

यह भी सही है कि कोई भी राष्ट्रपति, हालांकि, किसी विशेष पर्यावरणीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के कई तरीके खोज सकते हैं, जैसे कार्यकारी आदेश और अन्य उपाय। जिनमें से सभी अपने क्षेत्र में निरंतर ध्यान देने हेतु लगा सकते हैं, जिससे ऐसे मामले के लिए दुनिया भर में नजर रख सके। व्हाइट हाउस जो विज्ञान विरोधी और जीवाश्म ईंधन अधिक प्रभावी रूप मे उपयोग करने व पर्यावरण संरक्षण नीति (ईपीए) को नष्ट करना चाहता है, तो स्थिति बहुत ही अस्थिर हो जायेगी।

स्वच्छ जल अधिनियम नीति

1972 में स्वच्छ जल अधिनियम नीति को विकसित करने हेतु पारित किया गया था जिससे देश के जलमार्ग के प्रदूषण को कम किया जा सके। परंतु उस समय, देश की झीलों, नदियों और तटीय जल का लगभग दो-तिहाई हिस्सा मछली पकड़ने या तैरने जैसी गतिविधियों के लिए असुरक्षित हो गया था। यह देश का पहला और सबसे प्रभावशाली पर्यावरण कानूनों में से एक था। इस बीच, स्वच्छ वायु अधिनियम जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को खतरे में डालने वाले प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकने लिए बनाया गया है तथा दुनिया के सबसे व्यापक वायु गुणवत्ता कानूनों में से एक है। संघ के वैज्ञानिकों के अनुसार, इस अधिनियम ने खतरनाक प्रदूषण को काफी कम कर दिया है।

संगठन का कहना है कि स्वच्छ वायु अधिनियम ने 1980 के बाद से 25 प्रतिशत से अधिक, जमीनी स्तर के ओजोन, स्मॉग के एक खतरनाक घटक को कम करने मे मदद की है। इसने ओजोन परत मे छेद करने वाले रसायनों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने में भी मदद की है। ओजोन परत और गैसोलीन में सीसे की मात्रा को कम किया, जिससे 1980 के बाद से वायु प्रदूषण में 92 प्रतिशत की कमी आई है।

स्वच्छ वायु अधिनियम के नियमों ने उद्योगों को अत्याधुनिक समाधानों को विकसित करने और अपनाने के लिए प्रेरित किया है जो बिजली संयंत्रों, कारखानों और कारों से प्रदूषण को कम करते हैं, और इस प्रक्रिया में, संगठन का कहना है कि नई नौकरियां भी पैदा हुई हैं।

चेसेक अपनी बात जारी रखते है कि - हमें व्हाइट हाउस में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो यह समझ सके कि पर्यावरण नीति नकारात्मक तथा आर्थिक-विरोधी नीति नहीं है। दोनों को सह-अस्तित्व मे आना चाहिए और वह सह-अस्तित्व में आ सकते है। यदि आपका तर्क यह है कि सभी विनियमन खराब विनियमन है तो यदि आप सभी राज्यों को इसके लिये जिम्मेदारी दे देते है, तो वे राज्य अच्छी तरह से यह सब करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। जब संघीय धन में कटौती की जाती है, तो राज्यों को करों में वृद्धि करनी होगी या विनियमन और कार्यान्वयन को कम करना पडेगा। और यदि हम नियमों मे ढील देते हैं तो हम अधिक पर्यावरणीय आपदाओं को झेलेंगे। ट्रम्प जब वह कार्यालय में होते है तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वह ऐतिहासिक पेरिस समझौते के मसौदे को रद्द करने की कोशिश करते है और यह भी दावा करते है कि यह समझौता विदेशी नौकरशाहों के अंकुश अथवा नियंत्रण मे पहुंच जायेगा कि हम अमेरिका में कितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं।

वर्ष 2020 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन समझौता नीति के अनुसार वैश्विक औसत तापमान की वृद्धि मे पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान मे कमी लाना होगा। प्रत्येक भाग लेने वाले दुनियाभर के देशो को अपने स्वयं के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के योगदान को एक सीमा तक निश्चित करना पड़ेगा।

मई 2016 के पेरिस समझौते के तहत, कोई भी विदेशी नौकरशाह से लेकर राजा तक, अमेरिका के नियंत्रण का एक भी कोटा निरधारित नहीं कर सकता है। इस बारे में हमे निर्णय लेना होगा कि हम कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं या हमारी वास्तव में, समग्र ऊर्जा या जलवायु नीति क्या है। 190 से अधिक देशों के नेताओं ने समझौते का समर्थन किया। अतः अमेरिका के पास इसे रद्द करने की कोई अधिकार नहीं है। आप दुनिया भर के संप्रभु नेताओं को भी नहीं बता सकते हैं कि यह एक बहुपक्षीय समझौता नहीं है, जो उन्होंने दर्ज किया है। तो ट्रम्प के अकेले अन्यथा मसौदे से इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को पूरी दुनिया भर में देखा जा रहा है - नियमितरूप से तेजी से हो रही गंभीर बाढ़, जंगल की आग, गर्मी और तूफानो की बढोत्तरी पूरी दुनिया के लिये सबूत प्रदान कर रहे हैं जिसकी अनदेखी करना मुश्किल है-जब तक कि आप ट्रम्प जैसा व्योहार नहीं करते।

डोनाल्ड ट्रम्प की सोच जलवायु परिवर्तन के सभी वैज्ञानिक सबूतों के सामने एक छोटी मक्खी के बराबर है और आश्चर्य भी होता है कि क्या उन्होंने कभी पृथ्वी के तापमान रिकॉर्ड को व्यक्तिगत तौर से देखा है। यह कल्पना करना कठिन है कि कोई भी देश, विश्व मे घटित हो रही वर्तमान परिस्थितियो को गंभीरता से नहीं लेगा।

डेबोरा लॉरेंस, वर्जीनिया विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर है, कहते हैं कि पेरिस समझौता तभी प्रभावी होगा जब 55 प्रतिशत वैश्विक उत्सर्जन करने वाले देश इसे 'हां' कहेंगे, और अमेरिकी वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा अकेले बनाता हैं। अगर ट्रम्प इस समझौते से बाहर निकलते हैं, तो बाकी दुनिया आगे बढ़ जाएगी और जो उस प्रयास का हिस्सा नहीं हैं उसके लिये इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या होगी।

कोयला उद्योग के बारे में ट्रम्प के विचार

वेस्ट वर्जीनिया में प्रचार करते समय, ट्रम्प ने कोयला नौकरियों को वापस लाने का वादा किया है। यह एक ऐसा विचार है जो कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष मे सामान्य रूप से ऊर्जा के विकास मे कमी दर्शाता है, जबकि उर्जा के लिये कोयले के उपयोग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को अदेखा नही किया जा सकता है। लॉरेंस बताते हैं कि वर्तमान मे कोयले की अधिकांशतः नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, जो इस उद्योग के विकास का नकारात्मक परिणाम हैं। पिछले कुछ समय से बाजार, कोयले से प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। लॉरेंस कहते हैं, कोयला कम नही हुआ है क्योंकि हम सभी कोयले के प्रभाव के बारे में चिंतित हैं, और कोयले तक पहुंचने के लिए अब खदान कठिन से और कठिन हो रहा है। इस एक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो कोयले पर निर्भर है, बस कई टिप्पणियों में से एक यह है कि ट्रम्प ने उस राशि को आपदा के लिए एक नुस्खा बनाया है।

स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पर संक्रमण

गैरलाभकारी पर्यावरण इक्विटी निदेशक, सांचेज कहते हैं कि हमें एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पर हो रहे संक्रमण का पता लगाने की आवश्यकता है और वर्तमान ट्रम्प का नेतृत्व इसे बढ़ाने मे विश्वास नहीं रखता है। सांचेज ने कहते है कि पर्यावरण संरक्षण नीति (ईपीए) के बिना हम क्या करेंगे इसकी कल्पना भी नहीं की सकती है। भविष्य मे पर्यावरण असंतुलन बर्बादी के कगार पर पहुंच जायेगा।

जमीनी हकीकत यह है कि पर्यावरण नियमों, पर्यावरण कार्यक्रमों और राष्ट्र और दुनिया की मदद करने वाली एजेंसियों के प्रति ट्रम्प की शत्रुता न केवल विशाल क्षेत्रोंवाली आबादी के लिए विवादास्पद है, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्तित्व है जो उनपर ध्यान भी नही देना चाहते हैं जबकि अमेरिका को फिर से महान बनाने के अपने लक्ष्यपर जोर देने की चर्चा करते है। परंतु अमेरिका को निरंतर महानता की तरफ ले जाने के लिए ऊची सोच व दूर-दृष्टि की आवश्यकता है, नकि इस घड़ी को 50 साल पीछे पहुचाना। इसमे नवप्रवर्तनकर्ताओं, हरित-प्रौद्योगिकी और निरंतर विचारशील प्रगति को आगे बढ़ाना शामिल है, जो एक राष्ट्र के रूप में उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने मे सहायक रहे।

अगला अंक 6 भी अवश्य पढ़ें ....